

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 374/2013/जोधपुर.

मैसर्स इण्डिया एजेन्सी, रिया हाऊस, सोजती गेट, जोधपुर।अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर।प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कैलाशचन्द्र भण्डारी,

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.05.2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 68(1) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र संख्या उपाजो/कर-1/2012-13/127 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.01.2013 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 12.03.2012 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर किसी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं पाया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा संद्वारित लेखा पुस्तकों में अंतिम स्टॉक 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल ₹18,80,333/-, 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल ₹45,11,604/-, 15 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल ₹1,71,040/- की उच्चन्ति बिक्री व माह जनवरी 2012 व फरवरी 2012 का नियमित कर बकाया होना पाया गया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से करापवंचन का मामला होने से प्रकरण सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) को प्रेषित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 23.02.2012 के लिये दिनांक 30.03.2012 को नोटिस जारी किया गया। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.03.2012 को ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर, जवाब प्रस्तुत किया इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 22, 25(1) व 61 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2012 पारित करते हुए कुल कर राशि ₹8,04,659/-

लगातार.....2

एवं धारा 61 के तहत शास्ति ₹16,09,318/- व अधिनियम की धारा 22 के तहत नियमित कर, ₹3,59,378/- कुल ₹27,73,355/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी ने प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.03.2012 को प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर, कर एवं कर के बराबर शास्ति कुल ₹16,09,318/- के प्रशमन हेतु निवेदन किया गया। प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2013 से अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत दायर प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिस की पालना में नोटिस जारी किये जाने की दिनांक को ही कर निर्धारण अधिकार द्वारा निर्धारित किये गये कर को जमा करवाने की पेशकश कर, अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रस्तावित कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है, उक्त प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 33 पर उपलब्ध है। कथन किया कि तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.03.2012 को प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रशमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर नियमानुसार कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है तथा प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मनोवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यानुसार अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच में पाया गया गयी अनियमितताओं के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा निर्धारित कर जमा करवाये जाने की पेशकश कर, उसी दिन फैसला करने का निवेदन किया गया है, जिसे मद्देनजर रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों अनुसार कर एवं कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.03.2012 को प्रस्तुत किया गया, परन्तु प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2013 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अस्वीकार कर दिया। नैसर्गिक न्याय के स्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना में पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत भी व्यवहारी के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञापक है। नियम 48 उद्धरित करना सुसंगत होगा :-

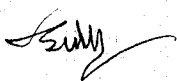
48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,-

Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

विधायिका ने वेट अधिनियम का प्रावधान 68 अनावश्यक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में फंसने से बचाने हेतु प्रावधित किया गया है। धारा 68 की सुसंगत उपधाराएं इस प्रकार हैं :-

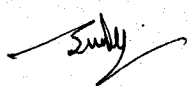
68. Composition of offences. -

- (1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.
- (2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.




- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (8) of section 75 or under sub-section (6) or (9) or (11) of section 76, the officer authorized under sub-section (4) of section 75 or the officers authorized under sub-section (4) of section 76 or Incharge of a check-post, as the case may be, may accept composition money from such person in lieu of penalty or prosecution, which shall be,—
- (a) in case of offence committed under sub-section (8) of section 75 or sub-section (6) of section 76, equal to the amount of four times of the tax leviable on the goods involved or twenty five percent of the value of such goods, whichever is less;
- (b) in case of offence committed by him under subsection (9) of section 76, equal to fifteen percent of the value of the goods;
- (c) in case of offence committed under sub-section (11) of section 76, equal to twenty five percent of the value of such goods.
- (4) The composition of any offence in lieu of penalty or prosecution under sub-section (2), shall be without prejudice to the liability of the person or dealer, charged with the offence, to pay the tax with interest so avoided or evaded or wrongly credited by him.
- (5) On the payment of the amount of composition determined under sub-section (2) and (3), no further proceeding under the provisions of this Act for imposition of penalty or launching of prosecution for the same offence, shall be initiated.
- (6) Notwithstanding anything contained in section 51, no amount of composition accepted and no amount of interest levied under this section, shall be waived or reduced by the Commissioner.
- (7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.

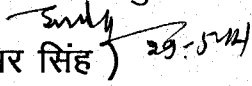
उपधारा (1) के तहत दायर प्रार्थना-पत्र को प्रशासनिक अधिकारी उपधारा (2) के तहत स्वीकार कर सकता है। इस प्रावधान में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के तहत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के अधिकार प्रदत्त हैं तथा 'may' शब्द उपयोग किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश में



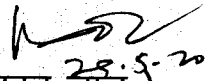

व्यवहारी के आवेदन को अस्वीकार किया है, लेकिन आदेश से पूर्व व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना विधिक आवश्यकता है। अतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रशासनिक अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदनकर्ता व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विधिसम्मत आदेश पारित करें।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह) 29-5-14

सदस्य


(मदन लाल) 28-5-2014

सदस्य